



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 25 फरवरी, 2016 ई0

फाल्गुन 06, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग-4

संख्या 121/XXX(4)/2016-04(03)/2016

देहरादून, 25 फरवरी, 2016

अधिसूचना

विविध

प0 आ0-38

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 233 सपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- नियम 2(ट) का संशोधन 2. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गये विद्यमान नियम 2 के खण्ड (ट) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

2(ट)—"उपयुक्तता जांच" से तात्पर्य मौखिक जांच, जो न्यायालय उचित समझे, से है।

नियम 5 के खंड 3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 5 के खंड (क) (क) तथा (ख) का तथा (ख) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

5(क)— सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) संवर्ग के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा;

(ख) सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) संवर्ग के सीमित प्रतियोगितात्मक चयन परीक्षा द्वारा;

नियम 6 के खंड 4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 6 के खंड (क) (क) तथा (ख) का तथा (ख) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

6(क)— पैसठ प्रतिशत (65 प्रतिशत) पदोन्नति द्वारा सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) के मध्य से श्रेष्ठता सह ज्येष्ठता के सिद्धान्त के आधार पर;

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

2(ट)—"उपयुक्तता जांच" से तात्पर्य नियम-20(3) के अनुसार विहित जांच से है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

5(क) पदोन्नति द्वारा भर्ती ऐसे स्थाई किये गये सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) के अधिकारियों में से नियम-20 के अनुसार विनिर्णीत श्रेष्ठता-सह-वरिष्ठता के आधार पर की जायेगी, जिन्होंने भर्ती वर्ष के कैलेण्डर वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) सीमित प्रतियोगितात्मक चयन परीक्षा से स्थाई किये गये ऐसे सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) संवर्ग के अधिकारियों में से जिन्होंने इस रूप में भर्ती वर्ष के कैलेण्डर वर्ष के प्रथम दिवस को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

6(क)— पैसठ प्रतिशत (65 प्रतिशत) पदोन्नति द्वारा सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) संवर्ग में से ऐसे स्थायी किये गये अधिकारियों में से जिन्होंने सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) के रूप में भर्ती वर्ष के कैलेण्डर वर्ष के प्रथम दिवस को न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, नियम 20 के अनुसार विनिर्णीत श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर;

परन्तु यह कि ऐसे न्यायिक अधिकारी जिन्हें दण्ड दिया गया हो, दण्ड दिये जाने के दिनांक से तीन वर्ष के लिए श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति और चयन के लिए विचार में नहीं लिये जायेंगे। यद्यपि ऐसे अधिकारी जिनके विरुद्ध

अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, विचार में लिये जायेंगे, किन्तु उनका परिणाम सीलबन्द लिफाफे में 01 वर्ष के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतिम निर्णय के अध्याधीन, जो भी पहले हो रखा जायेगा।

(ख) दस प्रतिशत (10%) सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) जिनका सेवाकाल 5 वर्ष से कम का न हो, की सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा जो पूर्णतः श्रेष्ठता के आधार पर हो, से पदोन्नति द्वारा;

(ख) दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) संवर्ग में से ऐसे स्थायी किये गये अधिकारियों में से जिन्होंने सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) के रूप में भर्ती वर्ष के कैलेण्डर वर्ष के प्रथम दिवस को जिनका सेवाकाल पांच वर्ष से कम का न हो, सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा जो पूर्णतः श्रेष्ठता के आधार पर होगी, से पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि ऐसे न्यायिक अधिकारी जिन्हें दण्ड दिया गया हो, दण्ड दिये जाने के दिनांक से तीन वर्ष के लिए श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति और चयन के लिए विचार में नहीं लिये जायेंगे। यद्यपि ऐसे अधिकारी जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, विचार में लिये जायेंगे, किन्तु उनका परिणाम सीलबन्द लिफाफे में 01 वर्ष के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतिम निर्णय के अध्याधीन, जो भी पहले हो रखा जायेगा।

नियम 8 का 5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर संशोधन स्तम्भ 2 में दिये गये नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

8 नियुक्तियों की संख्या:

(1) न्यायालय, समय-समय पर, किन्तु अंतिम भर्ती से जो तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् की न हों, विद्यमान एवं आगामी दो वर्षों में सम्भावित होने वाली रिक्तियों को ध्यान में रखते हुये रिक्तियों की संख्या भर्ती के समय नियत करेगा।

स्पष्टीकरण— पूर्वोल्लिखित उपनियम में वर्णित तीन वर्षों का प्रतिबन्ध, इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् की प्रथम भर्ती में लागू नहीं होगा।

(2) यदि किसी चयन में नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती से उपयुक्त चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, उस

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

8 की जाने वाली नियुक्तियों की संख्या:

न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति विद्यमान रिक्तियों एवं एक वर्ष के भीतर उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों जो सम्बन्धित भर्ती वर्ष के कैलेण्डर वर्ष में उत्पन्न होने वाली हो, को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष रिक्तियों को 31 मार्च अथवा उससे पूर्व अधिसूचित करेगी।

स्रोत से लिये जाने वाले संख्या से कम हो जिसकी भर्ती न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित की गयी है, तो न्यायालय तदनुरूप सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भर्तियों की संख्या बढ़ा सकेगा।

परन्तु यह कि रिक्तियों की संख्या जो पूर्वोल्लिखित उपनियम से भरी गई है, आगामी भर्ती के समय सीधी भर्ती के लिये आवंटित किये जाने वाले नियतांश (कोटा) की रिक्तियों की संख्या नियत किये जाते समय विचारणीय होगी और सीधी भर्तियों के लिये रिक्तियों की संख्या तदनुसार बढ़ायी जा सकेगी, तथापि सीधी सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रतिशत किसी भी दशा में सेवा के कुल सदस्य संख्या के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

नियम 18 का 6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गये विद्यमान नियम 18 के स्थान पर संशोधन

स्तम्भ 2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

18 सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा:

न्यायालय, जिला न्यायाधीश या कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा या विभागाध्यक्ष के द्वारा जैसी स्थिति हो, जिसके अधीनस्थ अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, समिति प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा भर्ती हेतु पात्र सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) जो नियम 20 के अंतर्गत प्रोन्नत नहीं किये गये हैं, के आवेदन आमंत्रित करेगा तथा प्रारूप जो इस उद्देश्य के लिये विहित किया गया हो, में भरा जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

18 सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा:

(1) मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा नियुक्ति के लिए आरक्षित रिक्तियों को अधिसूचित करेगी। इस प्रयोजन के लिए रजिस्ट्री विहित प्रारूप में मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति जैसा निर्देशित करे, सभी उपयुक्त अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी।

(2) रजिस्ट्री वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के अनुपात 1:3 में अर्ह अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी।

नियम 19 का 7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के उपनियम (1), (2) तथा (3) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये उपनियम (1), (2) तथा (3) रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(1) न्यायालय या समिति जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित की गयी हो, आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा करायेगी और परीक्षा आयोजित करायेगी।

(2) सीमित परीक्षा संपादित कराने के लिये नियम 17 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, पाठ्यक्रम परिशिष्ट "ग" में दिया गया है।

(3) यदि पात्र सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिये उपलब्ध न हों या न्यायालय की यह राय है कि सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) जो परीक्षा में सम्मिलित हुए हों परन्तु परीक्षा में अर्हता प्राप्त न कर पाये हों तब ऐसी अवशेष रिक्तियां अस्थाई रूप से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा को जा सकती है तथा उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा के अधिकारियों से प्रोन्नति जैसा कि नियम 20 में विहित है, भरी जा सकेंगी, जिनका समायोजन बाद में किया जायेगा।

नियम 20 का 8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गये विद्यमान नियम 20 के स्थान पर संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

20 उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति:

(1) मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति अधिकारीगण के अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता के सिद्धान्त के आधार पर प्रारम्भिक चयन करेगी। सूची में उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से दोगुने अधिकारीगणों के नाम शामिल होंगे।

(2) मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति पूर्व में उल्लिखित नियमों के आधार पर उपयुक्तता जांच हेतु सूची से उत्तराखण्ड

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) मुख्य न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा करायेगी और परीक्षा आयोजित करायेगी।

(2) सभी अभ्यर्थी जिनके नाम मुख्य न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति के द्वारा 1:3 के अनुपात में सूची में अन्तिम किये गये हो, लिखित परीक्षा में उपस्थित होंगे और परीक्षा का पाठ्यक्रम नियमों के परिशिष्ट "ग" के अनुरूप होगा।

(3) यदि किसी मामले में सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए आरक्षित रिक्तियां पर्याप्त अभ्यर्थियों या सफल अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होने के कारण नहीं भरी जाती है तो ऐसी रिक्तियां नियम 20 में यथाउपबंधित रीति से पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी, किन्तु नियम 22 में यथासंदर्भित ऐसी रिक्तियों की संख्या आगामी भर्ती में तैयार रोस्टर के अधीन पहली बार उत्पन्न होने वाली पदोन्नति के कोटे की रिक्तियों में से घटा दी जायेगी और सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के कोटे में बढ़ा दी जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

20 उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति:

(1) सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) के संवर्ग के सदस्यों से पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए चयन श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। श्रेष्ठता का मूल्यांकन नियम 20 के उपनियम (3) में एतदपश्चात् यथाउल्लिखित रीति के आधार पर किया जायेगा।

(2) 1:3 के अनुपात में अर्ह अधिकारियों की एक सूची उनके वरिष्ठता क्रम में न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा तैयार की जायेगी और इसे

न्यायिक सेवा के सदस्यों को बुलायेगी और उपयुक्तता साक्षात्कार के पश्चात मुख्य न्यायाधीश या पदोन्नति समिति के लिये योग्य पाये गये अधिकारीगण की सूची तैयार करेगी।

अधिकारियों की गोपनीय आख्या के साथ मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति के समक्ष रखा जायेगा। रजिस्ट्री ऐसे अधिकारियों के पांच दीवानी और पांच फौजदारी निर्णयों को भी मंगायेगी जो भर्ती वर्ष के 31 मार्च से पूर्व एक वर्ष की अवधि में उद्घोषित किये गये हो (अर्थात् पूर्व वर्ष के दिनांक 01 अप्रैल से दिये गये निर्णय) और उन्हें इस प्रकार तैयार की गई सूची के साथ मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति के समक्ष रखा जायेगा। यद्यपि मुख्य न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति के लिए यह विकल्प रहेगा कि वह अधिकारियों द्वारा दिये गये अन्य निर्णयों को भी मंगा सकेगी;

परन्तु यह कि जहां संबंधित न्यायिक अधिकारी ऐसे पद पर कार्यरत है, जहां निर्णय नहीं लिखे जाते हैं, जैसे प्रतिनियुक्ति पर उच्च न्यायालय में या किसी अन्य प्राधिकारी पद पर या फोरम या सरकार इत्यादि में, वहां 'पिछले एक वर्ष' से अभिप्राय उसके उपर्युक्त पद पर प्रतिनियुक्ति से पहले का एक वर्ष जिसमें उसने निर्णय लिखे हैं, अर्थात् 'इस प्रकार का एक वर्ष' जिस वर्ष में उसने ऐसा पद धारण किया हो, जिस पद पर उसके द्वारा निर्णय लिखे जाने थे, होगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई अर्ह अधिकारी सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) के पद को धारण कर रहा हो और फौजदारी क्षेत्राधिकार न रखता हो तो फौजदारी निर्णयों के लिए 'एक वर्ष' की वह अवधि होगी जिसमें उसके पास फौजदारी मामलों की क्षेत्राधिकारिता थी। इसी प्रकार यदि कोई अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत है और दीवानी मामलों में कोई क्षेत्राधिकारिता नहीं हो तो 'एक वर्ष' की वह अवधि होगी जिसमें उसके पास दीवानी मामलों की क्षेत्राधिकारिता थी।

(3) उपयुक्तता जांच/श्रेष्ठता के मूल्यांकन के मानक

(क) उनके निर्णयों का मूल्यांकन — 40 अंक

(ख) अंतिम पांच वर्षों के लिए वार्षिक गोपनीय आख्याओं का मूल्यांकन — 30 अंक

उपयुक्तता परीक्षण का अन्य भाग अभ्यर्थी की निरन्तर दक्षता का आंकलन होगा, जो उसके उपयुक्तता आंकलन से विगत पांच वर्ष के सेवा अभिलेखों के आधार पर विनिर्णित किया जायेगा।

इस भाग के लिए अंकों की रीति निम्नवत होगी—

उत्कृष्ट — 6 अंक

अति उत्तम — 5 अंक

उत्तम — 4 अंक

संतोषजनक/औसत/अच्छा — 3 अंक

खराब — कोई अंक नहीं

(ग) मौखिक परीक्षा — 30 अंक

अंतिम प्राप्त अंक औसत की प्रक्रिया द्वारा संबंधित अभ्यर्थी/अधिकारी द्वारा प्राप्त कुल अंकों को विभाजित करके निकाले जायेंगे।

(4) सूची में सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) के संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली अपेक्षित रिक्तियों की संख्या के दोगुने अधिकारियों के नाम होंगे।

(5) चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन के लिए उनके समक्ष रखी जायेगी और उच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ रखी जायेगी।

(6) अनुमोदित सूची का परीक्षण न्यायालय करेगा और पदोन्नति के लिए अंतिम चयन करेगा तथा उसे राज्यपाल को अग्रसरित करेगा।

नियम 22 का 9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 22 के स्थान पर संशोधन

स्तम्भ 2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

22 नियुक्ति:

(1) नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर राज्यपाल सेवा में नियुक्ति करेंगे लेकिन सीधी भर्ती

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

22 नियुक्ति एवं ज्येष्ठता:

(1) सेवा में नियुक्ति, दस-दस पद के दो खण्डों वाली, बीस बिन्दु रोस्टर प्रणाली के

के मामले में चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सीय परीक्षण के उपरान्त ही नियुक्ति होगी।

आधार पर की जायेगी। प्रथम खण्ड के दस पदों में से प्रथम और द्वितीय रिक्ति पदोन्नति कोटा अर्थात् नियम 6 (क) के अन्तर्गत भरी जायेगी, तीसरी रिक्ति सीधी भर्ती के कोटे से अर्थात् नियम 6(ग) के अन्तर्गत भरी जायेगी; चौथी रिक्ति सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कोटे अर्थात् नियम 6(ख) के अन्तर्गत भरी जायेगी; पांचवी और छठवीं पदोन्नति कोटे से अर्थात् नियम 6(क) के अन्तर्गत भरी जायेगी; सातवी सीधी भर्ती की सूची से अर्थात् नियम 6(ग) के अन्तर्गत भरी जायेगी; आठवीं और नवीं पदोन्नति कोटे से अर्थात् नियम 6(क) के अन्तर्गत भरी जायेगी; दसवीं सीधी भर्ती कोटे से अर्थात् नियम 6(ग) के अन्तर्गत भरी जायेगी। दस पदों के दूसरे बैच में ग्याहरवीं और बारहवीं पदोन्नति कोटे से अर्थात् नियम 6(क) के अन्तर्गत भरी जायेगी; तेरहवीं सीधी भर्ती कोटे से अर्थात् नियम 6(ग) के अन्तर्गत भरी जायेगी; चौदहवीं सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कोटे से अर्थात् नियम 6(ख) के अन्तर्गत भरी जायेगी; पन्द्रहवीं और सोलहवीं पदोन्नति कोटे अर्थात् नियम 6(क) के अन्तर्गत भरी जायेगी; सतरहवीं सीधी भर्ती कोटे से अर्थात् नियम 6(ग) के अन्तर्गत भरी जायेगी और अठारहवीं, उन्नीसवीं और बीसवीं पदोन्नति कोटे से अर्थात् नियम 6(क) के अन्तर्गत भरी जायेगी।

(2) सेवा में नियुक्ति, दस-दस पद के दो खण्डों वाली, बीस बिन्दु रोस्टर प्रणाली के आधार पर की जायेगी। प्रथम खण्ड के दस पदों में से प्रथम छः पद नियम 6 (क) के अनुसार भरे जायेंगे, आगामी तीन पद नियम 6(ग) के अनुसार भरे जायेंगे, अन्तिम पद नियम 6(ख) के अनुसार भरे जायेंगे, द्वितीय खण्ड के दस पदों में से प्रथम सात पद नियम 6(क) के अनुसार भरे जायेंगे, आगामी दो पद नियम 6(ग) के अनुसार भरे जायेंगे। अंतिम पद नियम 6(ख) के अनुसार भरे जायेंगे।

(2) नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर राज्यपाल सेवा में नियुक्ति करेंगे किन्तु सीधी भर्ती के मामले में चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सीय परीक्षण के उपरान्त ही नियुक्ति होगी;

जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, वरन् उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता प्राप्त होगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस

वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम अन्य नियुक्त व्यक्तियों के चक्रानुक्रम में सबसे ऊपर रखा जायेगा।

नियम 25क का 10. मूल नियमावली में नियम 25 के पश्चात् एक नया नियम 25क शीर्षक सहित अंतःस्थापन कर दिया जायेगा, अर्थात्—

“25क— लोक हित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बंधित विशेष उपबंध:

(1) उत्तराखण्ड राजकीय कर्मचारियों पर लागू सेवा नियमों में उपबंधित उपबंधों की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी कोई अधिकारी जो इस सेवा में है, जिसने 50 वर्ष, 55 वर्ष और 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, यदि ऐसे अधिकारी के अभिलेखों के आंकलन और मूल्यांकन पर उच्च न्यायालय की दृष्टि में यह है कि ऐसा अधिकारी 50 वर्ष, 55 वर्ष और 58 वर्ष जैसी स्थिति हो, के पश्चात् सेवा में बने रहने के लिए उचित एवं उपयुक्त नहीं है तो उसे तीन माह से अनधिक अवधि की लिखित सूचना या ऐसी सूचना के स्थान पर तीन माह का वेतन तथा भत्ते देते हुए लोक हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को उपनियम (1) के अधीन लोक हित में सेवानिवृत्त किया जाये अथवा नहीं, इसका विचारण न्यूनतम तीन बार अर्थात् जब वह 50 वर्ष, 55 वर्ष और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला होगा, तब-तब किया जायेगा।

परन्तु यह कि उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यह नहीं माना जायेगा कि किसी अन्य समय पर किसी सदस्य की सेवा के लिए न्यायालय द्वारा ऐसे विचार को प्रतिषेध किया गया है।

नियम 26 का 11. मूल नियमावली में नियम 26 को निरसित कर दिया जायेगा।
निरसन

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of “the Constitution of India”, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 121/XXX(4)/2016-04(03)/2016, Dehradun, dated February 25, 2016 for general information:

No. 121/XXX(4)/2016-04(03)/2016

Dated Dehradun, February 25, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by Article 233 read with proviso to Article 309 of the “Constitution of India” the Governor is pleased to make the following Rules with a view to further amend the Uttaranchal Higher Judicial Service Rules, 2004:-

The Uttarakhand Higher Judicial Service (Amendment) Rules, 2016

Short title and commencement 1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Higher Judicial Service (Amendment) Rules, 2016.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of clause (i) of rule 2 2. In clause 2 (i) of the principal rules, for set out in column 1 below, the clause as set out in column-2 shall be substituted namely

2(i) - "Suitability test" means oral test which the Court deems fit. "Suitability test" means test as prescribed in rule 20(iii).

Amendment of clauses (a) and (b) of rule 5 3. In clause (a) and (b) of the principal rules of rule 5, set out in column 1 below, the clauses as set out in column-2 shall be substituted namely-

Column-1**Existing Rule**

5(a): By promotion from amongst the cadre of civil judge (Senior Division);

(b) By selection through limited competitive examination from amongst Civil Judges (Senior Division) cadre;

Amendment of clause (a) and (b) of rule 6 4.

In the principal rules, for clause (a) and (b) of rule 6, set out in column 1 below, the clauses as set out in column-2 shall be substituted namely-

Column-1**Existing Rule**

6(a): Sixty Five percent by promotion by amongst the Civil Judges (Senior Division) on the basis of principle of merit-cum-seniority;

Column- 2**Rule hereby substituted**

5(a) By promotion from amongst the confirmed officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division), having minimum 5 years of service as such on the first day of the calendar year of recruitment on the basis of merit-cum-seniority to be judged as per rule-20.

(b) By selection through limited competitive examination from amongst the confirmed officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division) having minimum five years of service as such on the first day of the calendar year of recruitment.

Column- 2**Rule hereby substituted**

6: (a) Sixty five percent by promotion from amongst the confirmed officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division), having minimum 5 years of service as such in the cadre of Civil Judge (Senior Division) on the basis of principle of merit-cum- seniority, to be judged as per rule-20 on the first day of the calendar year of recruitment.

Provided that Judicial officer, who has been awarded penalty, shall not be considered for promotion and selection on the basis of merit-cum-seniority, for three years from the date of award of penalty. However, such officer, who is facing

(b) Ten percent by promotion strictly on the basis of merit through limited competitive examination of Civil Judges (Senior Division) having not less than five years Service as Civil Judge (Senior Division);

disciplinary action, shall be considered, but his result shall be kept in sealed cover for one year subject to the final outcome of the disciplinary proceeding, whichever is earlier.

(b) Ten percent by promotion strictly on the basis of merit through limited competitive examination from amongst the confirmed Civil Judges (Senior Division) having not less than five years Service as such on the first day of the calendar year of recruitment;

Provided that the Judicial officer, who has been awarded penalty, shall not be considered for selection through limited competitive examination for three years from the date of award of penalty. However, such officer, who is facing disciplinary action, shall be considered, but, his result shall be kept in sealed cover for one year subject to the final outcome of the disciplinary proceeding, whichever is earlier.

Amendment of 5. In rule 8 of the principal rules, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted namely--

Column-1

Existing Rule

8 : Number of appointment to be made-

(i) The Court, shall, time to time, but not later than three years from the last recruitment, fix the number of vacancies to be taken at the recruitment, keeping in view the existing and likely to occur vacancies in the next two years.

Explanation- The limitations of three years mentioned in the forgoing sub-rule shall not applied to the first recruitment held after the enforcement of these rules.

(ii) If at any selection the number of suitable selected direct recruits available for appointment is less than the number vacancies of determined by the Court to be taken from that source, the court may increase correspondingly the number of vacancies to be taken by promotion from the Civil Judge (Senior Division) cadre;

Column- 2

Rule hereby substituted

8 : Number of appointment to be made-

The Court or the Committee constituted by the Chief Justice shall notify the vacancies on or before 31st March of every year keeping in view the existing vacancies and future vacancies that may arise within one year ending with the concerned calendar year.

Provided that the number of vacancies filled in the forgoing sub-rule shall be taken into consideration while fixing the number of vacancies to be allocated to the quota of direct recruits at the next recruitment and the number of vacancies for direct recruitments may be raised accordingly; howsoever, that the percentage of direct recruits in the service does not in any case exceed 25 percent of the total strength of the service.

Amendment of 6. In rule 18 of the principal rules, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted namely-

Column-1

Column-2

Existing Rule

Rule hereby substituted

18: Limited competitive examination-

The applications for recruitment through limited competitive examination of eligible Civil Judge (Senior Division), who have not been promoted under rule 20 shall be invited by the Court through the district judge or through the Head of the office or Head of the Department as the case may be under those subordination the candidate works and shall be made in the form, prescribed for that purpose.

18: Limited competitive examination-

- (i) The Chief Justice or the Committee constituted by the Chief Justice shall notify the vacancies reserved for appointment by limited competitive examination. The applications shall be invited from all the eligible candidates by the Registry as directed by the Chief Justice or Committee constituted by the Chief Justice in the form prescribed for that purpose.
- (ii) The Registry shall prepare the list of the eligible candidate in the ratio of 1:3 of the available vacancies on the basis of seniority.

Amendment of 7. In Clause (i), (ii) and (iii) of the principal rule 19, set out in column-1 below, the clauses as set out in column-2 shall be substituted namely-

Column-1

Column-2

Existing Rule

Rule hereby substituted

(i) The Court or Committee constituted by the Chief Justice may get these applications scrutinized and may hold the examination.

(ii) Provision of rule 17 shall apply mutatis mutandis for conducting the limited competition. The Syllabus is given in Appendix "C".

(i) The Chief Justice or Committee constituted by the Chief Justice may get these applications scrutinized and may hold the examination.

(ii) All the candidates, whose names are in the list finalized by the Chief Justice or Committee constituted by the Chief Justice in the ratio of 1:3, shall appear in the written

(iii) In case eligible Civil Judge (Senior Division) are not available for the limited competitive examination or the Court is of the opinion that the Civil Judge (Senior Division), who appeared have not qualified the test, such remaining vacancies may be reverted temporarily to the Uttarakhand Judicial Service and may be filled through promotion amongst the officers of Uttarakhand Judicial Service as provided under rule 20, which shall be adjusted later on.

examination and the syllabus of the examination shall be as per Appendix "C" of the rules.

(iii) In case, vacancies reserved for limited competitive examination are not filled-up by reason of sufficient candidates not being available or found successful, the same may be filled-up by way of promotion as provided in rule-20. However, in the subsequent recruitment, such number of vacancies shall be deducted from the quota of promotees for the first time the vacancies arise under the roster prepared as referred to in rule 22 and will be added in the quota for limited competitive examination.

Amendment of 8. In rule 20 of the principal rule, set out in column 1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely-

Column-1

Existing Rule

20: promotion of members of the Uttarakhand Judicial Service-

(i) The Chief Justice or Committee constituted by the Chief Justice shall, after examining the record of the officers make a preliminary selection of the officers on the basis of principle of merit-cum-seniority.

The list shall contain the names of officers twice the number of vacancies required to be filled by promotion of the members of the Uttarakhand Judicial Services.

(ii) The Chief Justice or Committee nominated by the Chief Justice shall call the members of Uttarakhand Judicial Services of the list prepared in the forgoing rule for the suitability test and after the suitability test, the Chief Justice or Committee shall prepare a list of officers found suitable for the promotion.

Column- 2

Rule hereby substituted

20: promotion of members of the Uttarakhand Judicial Service-

(i) Recruitment by promotion from the members of the cadre of Civil Judge (Senior Division) shall be made by selection by the Chief Justice or Committee constituted by Chief Justice on the principle of merit-cum-seniority. Merit shall be evaluated on the basis of criteria as mentioned hereinafter in sub rule(iii) of rule 20.

(ii) The Registry of the Court shall prepare a list of eligible officers in the ratio of 1:3 in order of their seniority and shall place it before the Chief Justice or Committee constituted by the Chief Justice along with the ACRs of the officers. The Registry shall also call for 5 civil as well as 5 criminal judgments of such officers delivered by them within the period of one year prior to 31st March of the year of commencement of recruitment (i.e. from 1st April of the previous year) and shall place it before the Chief Justice or Committee constituted by the Chief Justice along with the list so prepared. However, it would be open to the Chief Justice or Committee constituted by the Chief

Justice to call for other judgments delivered by the officers.

Provided that where the concerned Judicial officer is working on a post in which he does not have to write judgments such as a deputation, post in the High Court or in any other authority or Forum or Government etc., the expression "last one year" shall be construed as the last one year prior to his aforesaid posting on deputation, meaning thereby "such a year" in which he was occupying a post/holding an appointment in which he had to write judgments.

Provided further that if the eligible officer is holding the post of Civil Judge (Senior Division) and is not having criminal jurisdiction, then for criminal judgments 'one year' shall be construed for the period he was having jurisdiction over the criminal matters. Likewise, if the officer is posted as Chief Judicial Magistrate and has no jurisdiction over civil matters, then for civil judgments one year shall be construed for the period he was having jurisdiction over civil matters.

(iii) Norms for suitability test/evaluation of merit-

(a) Evaluation of their judgments-40 marks

(b) Evaluation of Annual Confidential Reports for the last five years- 30 marks

The other part of the suitability test will be the assessment of the candidate for his continued efficiency which will be adjudged on the basis of his service record of preceding 05 years of the suitability test.

The marking pattern shall be as follows for this section-

Outstanding	- 6 marks
Very Good	- 5 marks
Good	- 4 marks
Satisfactory /Average/ Fair	- 3 marks
Poor	- No marks
(c) Oral Test -	30 marks

The final marks obtained shall be worked out by process of averaging, that is to

say, by dividing the gross total marks obtained by respective candidate/ officer.

(iv) The list shall contain the name of the officers twice the number of vacancies required to be filled up by promotion from the cadre of Civil Judge (Senior Division).

(v) List prepared by the Selection Committee shall be placed before the Chief Justice for his approval and shall be placed for consideration before the Court.

(vi) The Court shall examine the approved list and make a final selection for promotion and forward the same to the Governor.

Amendment of 9. In rule 22 of the principal rules, set out in column 1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely-

Column-1

Existing Rule

22: Appointment-

(i) The Governor shall on receipt of the list of candidates make appointment to the service but in case of the direct recruitment after character verification and medical examination.

Column- 2

Rule hereby substituted

22: Appointment and Seniority-

(i) Appointment and seniority to the service shall be made on a 20 point roster with two blocks of 10 posts each. In the first block of 10 posts, the first and second vacancy shall be filled up from the promotion quota i.e. under rule 6(a); third vacancy shall be filled up from the quota of direct recruits i.e. under rule 6(c); the fourth vacancy shall be filled up from the limited competitive examination quota i.e. under rule 6(b); fifth and sixth shall be filled up from the promotion quota i.e. under rule 6(a); seventh shall be filled up from the list of direct recruits i.e. under rule 6(c); eighth and ninth shall be filled up from promotion quota i.e. under rule 6(a); tenth shall be filled up from direct recruits quota i.e. under rule 6(c). In the second batch of 10 posts the eleventh and twelfth shall be filled up from promotion quota i.e. under rule 6(a); thirteenth shall be filled up from direct quota i.e. under rule 6(c); fourteenth shall be filled up from limited competitive examination quota i.e. under rule 6(b); fifteenth and sixteenth shall be filled up from promotion quota i.e. under rule 6(a); seventeenth shall be filled up from direct recruits quota i.e. under rule 6(c); and eighteenth, nineteenth and twentieth shall be filled up from promotion quota i.e. under rule 6(a).

(ii) Appointment to the service shall be made on a 20 point roster with two blocks of 10 points each. In the first block of 10 points, the first 6 posts shall be filled up from those appointed under rule 6(a); and the next 3 posts from those appointed under rule 6(c), and the last post from those appointed under rule 6(b). In the second block of 10 posts, the first 7 posts shall be filled from those appointed under rule 6(a); the next 2 posts from those appointed under rule 6(c), and the last post from those appointed under rule 6(b).

(ii) The Governor shall on receipt of the list of candidates make appointment to the service but in case of the direct recruitment after character verification and medical examination.

Where appointments from any source fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so, however, that their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order of the other appointees.

Insertion of a new rule 25A

10. After rule 25 of the principal rules, a new rule 25A with the following title shall be inserted, namely-

" 25A- Special provision regarding compulsory retirement in public interest-

(i) Notwithstanding anything contained in these rules and without prejudice to the generality of the provisions contained in the Service rules applicable to Government Servants in Uttarakhand, an officer borne in this service who has attained the age of 50 years, 55 years and 58 years may compulsorily be retired in public interest by giving him notice of not less than 'Three months' in writing or 'Three months' pay and allowances in lieu of such notice, if the High Court on an assessment and evaluation of the record of such officer is of the view that such officer is not fit and eligible to continue in service beyond the age of 50 years, 55 years and 58 years, as the case may be.

(ii) Whether a member of the service should be retired in public interest under sub-rule (i) shall be considered at least three times, that is when he is about to attain the age of 50 years, 55 years and 58 years:

Provided that nothing in sub-rule (ii) shall be construed as preventing such consideration by the Court of a member of the service at any time other than those mentioned therein."

Omission of rule 26 11. Rule 26 of the principal rules shall be omitted.

By Order,

RADHA RATURI,
Principal Secretary.